One aspect of it is, do we really know when we acquire the technology that we are going to use it, I mean the technology acquisition and the feasibility of its use? Second aspect relates to training of pilots. How are we going to break this resistance to technological change so far as the Indian Airlines is concerned, with regard to pilots category?

SHRI SHIVRAJ PATIL: It is a very good question and I would like to answer it by saying that whenever we induct new technology, as far as the aircraft is concerned and ground facilities are concerned, we, in many cases, try to see that appropriate requisite training is also given to those who have to use it. Supposing we are inducting Air-bus 320. Then we have to train pilots also for that purpose. But at times when some instruments of advanced nature become available and we induct those instruments into this system, we have to train the users also at the same time, and if it becomes necessary to withdraw them, it affects the flying also, but generally when we have a project and a package, and we get the sophisticated instruments, at the same time we make provision for training also.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Sir, I believe that we have both the technology and the training because recently I read a report that we have three simulator centres, two at Hyderabad and one at Bombay...

MR. CHAIRMAN: This is about instrument landing facility in Delhi.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Yes, I am coming to that. In three major aircraft, it was shown that we have the technology and training in this country about instrument landing facility in India, in a perfect form. In spite of it, why is it not being done at Delhi airport, is the question. My question is, have we taken 100 per cent peformance guarantee of the crucial landing instrument purchased for the Delhi airport or not ? That is where the shoe pinches. These are very sophisticated and very costly instruments, and we have purchased and installed them. But have we taken 100 per cent performance guarantee ?

SHRI SHIVRAJ PATIL: This is a very sophisticated area and the technology is advancing everyday. Now, as far as, the training of the pilots on the simulators etc. is concerned, to some extent, this kind of training is given to them. But then, training has to be commensurate with sophistication of the instrument, and if the instrument is more sophisticated, then provision of simulator becomes difficult. The simulators which we have, I am not sure but as far as my understanding goes, do not provide for this kind of training.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I have myself seen...

MR. CHAIRMAN: They are different types.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Boeings I have seen; Jumbo Jets I have seen...

MR. CHAIRMAN: These instruments are only in Delhi.

SHRI SHIVRAJ PATIL: As far as the second part is concerned, I would like to say that whenever we take instruments, we get the warranty from them that the instrument will work and with that kind of clause in the contract, provisions are made.

MR. CHAIRMAN : Next question.

Projects undertaken abroad by IAAI

*109. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of CIVIL

AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether International Airports Authority of India is undertaking projects abroad whereby it would provide consultancy services and execute projects;

(b) if so, wha t are the details thereof; and

(c) what are the names of the countries where these projects would be undertaken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) to (c) The Malaysian Government has decided to award the work of construction of a full-fledged airport at Sibu to the IAAI on negotiated basis. The IAAI has filed the tender which will form basis of negotiations. The project cost is likely to be around Rs. 40 crores.

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, इस मंत्रालय के अंतर्गत करीब 6-7 सरकारी प्रतिष्ठान हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है यह पब्लिक लोग जानते हैं कि सभी प्रतिष्ठानों की हालत बिगड़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि मलेशिया सरकार ने भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कार्य देने का जब निर्णय ले ही लिया, जब कंट्रेक्ट देने का उन्होंने निर्णय ले ही लिया और लागत की रकम भी आपने अपने उत्तर में बताकर साफ कर दिया है तो फिर बात-चीत किन बातों पर की जायेगी? इसी का दूसरा भाग यह है कि क्या आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है जिससे कि आप विदेशों में यह एयरपोर्ट बना सकें?

श्री सभापति : कई जगह बना चुके हैं।

श्री शिवराज पाटिल : मैं श्रीमन्, माननीय सदस्य की मालूमात के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिविल एविएशन के तहत जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी ही एक ऐसी अंडरटेकिंग है जिसने करीब-करीब 100 करोड़ के जितना प्रोफिट बनाया है और आपको यह सुनकर खुशी होगी कि इंडियन एयरलाईन्ज ने भी प्रोफिट बनाया है और एयर इंडिया भी प्रोफिट बना रही है।

श्री रजनी रंजन साहू : प्रोफिट में और जनता की सुविधा में, दोनों का तालमेल बैठाइये?

श्री सभापति : अच्छे हैं, तभी तो दूसरे लोग कंट्रेक्ट देते हैं।

श्री शिव राज पाटिल : आपने शुरुआत ही ऐसा किया कि हमारी सारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज खराब है, इसलिए मैं आपको मालूमात के लिए, आपको खुशी हो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी ने दूसरी 5-6 जगहों पर एयरपोर्ट बनाने का काम लिया है और पूरा किया है। सिर्फ पूरा किया है ऐसा नहीं है उनके समाधान से काम किया है और उसमें उनको 20-25 करोड़ रुपये तक का प्रोफिट भी मिला है मलेशिया के लोगों ने लैटर आफ इंटेंट दिया है। लैटर आफ् इंटेंट देने के बाद उनके साथ चर्चा हो रही है और चर्चा होने के बाद कंट्रेक्ट पूरा मिलने के बाद यह काम हो जाता है। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि सोवियत यूनियन से भी इस अथारिटी को काम मिलने के बारे में चर्चा हुई है और हो सकता है इस अथारिटी को काम मिलेगा। बाहर के देश इसकी वाह-वाह करते हैं।

श्री सभापति : मैं बता देता हूं आपको कि इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है।

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, मैं इस मत का हूं कि बाहर के देशों में काम किया जाए।

श्री सभापति : यह जो अथारिटी है थ्रूआउट द वर्ल्ड इसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है।

श्री रजनी रंजन साहू : यह है, लेकिन इनसे पूछा था..(**व्यवधान**)

श्री मिर्जा इर्शादबेग : वाह की जगह इनके मुंह से आह निकल रही है।

श्री रजनी रंजन साहू : और जो उत्तर में इन्होंने कहा है कि बात-चीत की जायेगी, जब सब बात तय हो गई है तो फिर अब किन मुद्दों पर बात-चीत करना बाकी है इसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया? इन्होंने आंकड़ा तो इंडियन एयरलाईन्ज़ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी का दे दिया लेकिन एयर इंडिया का आंकड़ा नहीं दिया और यह जो मुनाफा हुआ है इंडियन एयरलाइन्ज़ का, यह इसमें जो यात्री हैं उनकी सुविधा-असुविधा के तालमेल को रखते हुए हुआ है या नहीं? यह खुशी की बात है कि प्रोफिट हुआ है, लेकिन सुविधा की तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए?

श्री सभापति : आप सवाल तक सीमित रहिए, इधर-उधर मत जाइये।

श्री रजनी रंजन साहू : मैंने इनसे पूछा था कि बात-चीत की जायेगी वह किन मुद्दों पर की जायेगी, यह स्पष्ट करें और क्या यह टर्न-की बेसिस पर बनाया जा रहा है या इसके और क्या टर्म्ज़ एंड कंडीशज़ हैं? इसका क्या ब्यौरा है, यह बात हम जानना चाहेंगे?

श्री शिव राज पाटिल : आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। यह लैटर आफ् इंटेंट उनके पास से आया है, कंट्रैक्ट हमारा साइन होने का है। कंट्रैक्ट साइन होने के बाद उसकी क्लाजेज़ को देखा जाता है। जब भी कभी ऐसी चर्चा हुई है तो पहले वह कहते हैं कि हम आपसे काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद डिटेल्स दिए जाते हैं, उनकी तरफ से प्रोपोजल आता है, हमारी तरफ से प्रोपोजल जाता है। उनकी चर्चा होने के बाद टर्म्ज़ आफ् कंट्रैक्ट फिक्स होते हैं। उसके बेसिज़ पर काम चलता है।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, I am very pleased to note that the hon. Minister has given good certificates to the Airlines that we are running in this country....

MR. CHAIRMAN: The question is about Airport Authority.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: ... including the Airport Authority.

MR. CHAIRMAN: You restrict yourself to the question.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: But the fares had recently gone up. Now it has been announced that the fares are going up in this country. My question is, if operating and giving consultancy and making airports abroad is a good foreign exchange earner for the country, this matter should be expanded. If it is expanded and we are able to earn more foreign exchange to buy more jet fuel and have better facilities for the country, then perhaps it may not be necessary to increase the fares. I would like to know from the hon. Minister whether he has made a perspective plan for the next five or ten years on what expansion we can possibly have in this direction and what facilities, as a result of that, will accrue to the passengers in India.

श्री शिवराज पाटिल : सर, यह जो सवाल हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एअरपोर्ट अथारिटी

से दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बना है और उसके फेज टू और फेज थ्री का भी काम चल रहा है। बंबई में डोमेस्टिक टर्मिनल का भी काम चल रहा है और वहां के इंटरनेशनल टर्मिनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मद्रास के अंदर इस अथोरिटी की मदद से डोमेस्टिक टर्मिनल ऐसा बना है जो हमारे देश का सबसे अच्छा और इंटरनेशनल टर्मिनल भी बनने जा रहा है। उसके साथ साथ कलकत्ता में भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनाने का काम चालू है। जो सुविधाएं इस अथोरिटी की मदद से देनी है, वह सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। मगर जो पहली बात आपने कही, आप मेरे से सहमत होंगे कि अगर यू०एस०ए० जैसे देश में, युनाइटेड स्टेटस आफ अमरीका में आपके फेयर पे दो गुना, तीन गुना, चार गुना फेयर ज्यादा हैं, जहां कि हवाई जहाज बनता है वहां पेट्रोल बनता है, वहां टेक्नोलोजी बनती है, वहां सारी चीजें यहां से ज्यादा हैं...

श्री समापति : आप फेयर पर मत जाइए, केवल अथोरिटी पर रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर–110...

बांसपानी-दैतरी रेल लाइन

*110. **श्री बैकुंठ नाथ साहू :** क्या रेल मंत्री 31 अगस्त, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4070 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी समय से लंबित बांसपानी-दैतरी रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई जांच की है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और इसके पूरा होने पर देश के राष्ट्रीय राजकोष में वृद्धि हो सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) पारादीप पोर्ट के रास्ते दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात की परियोजना के भाग के रूप में सम्बन्धित मंत्रालयों तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लाइन के निर्माण के प्रस्ताव की जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Sir, as regards part (b) of my question, the answer of the hon. Minister is not clear. The project was to be completed in three phases. Number one phase has been completed and the other phases have not yet been resumed. I want to know from the Hon. Minister whether the other phases will be resumed or not.

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमान्, जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, यह जंगपूरा से बांसपानी की 176 किलोमीटर की दूरी थी और इसका प्रस्ताव सन् 1974 और 1975 में किया गया था । उसके बाद एक खण्ड जंगपूरा और दैतारी के बीच का, 33 किलोमीटर की दूरी को सन 1981 में पूरा करके खोल दिया गया और उसके लिए यह तय हुआ था कि दैतारी के आसपास की जो खनिज खाने हैं, उससे लाभ हमको मिलेगा, उससे व्यापार करेंगे, लेकिन उसका उत्तर सही नहीं आया !...

MR. CHAIRMAN : The Question Hour is over.

———